अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

2048. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या प्रधान मंत्री 3 दिसंबर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1105 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : उच्चतम न्यायालय ने 13-11-1991 को 1989 की रिट याचिका सं० 1022 में दिए गए अपने निर्णय में यह इच्छा व्यक्त की थी कि भारत सरकार को, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की साध्यता पर विचार करना चाहिए । सरकार ने, 9-1-1992 को पुर्नविलोचन अर्जी फाइल की जिसमें निदेशों को सिफारिश में परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना की गई थी । उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विलोकन अर्जी को सुनने के पश्चात् 24-8-93 के अपने निर्णय में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :-

यदि पुनर्विलोकन अर्जी उठाए आक्षेपों पर आयोग ने पूर्ण रूप से कार्रवाई कर ली है तो सलाह दिए जाने पर भारत संघ, की गई चर्चा, और विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, मामले में पहल कर सकेगा । भारत संघ द्वारा पहल किए जाने पर ही अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए संविधान के अनुच्छेद 312 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

Transfer of Judges from the Courts where their wards are practising

2049. SHRI S. S. AHLUWALIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Justice of India has decided to transfer Judge from the Courts where their wards are practising throughout the country, particularly at the High Court level;

(b) if so, what are the details thereof ;

(c) whether Government propose to enforce the decision of the Chief Justice of India, if not, the reasons therefor ;

(d) if the answer to part (c) above be in the affirmative, whether every judge of a High Court will have to give a declaration that his ward is not practising in the High Court of which he is a judge ; and

(e) what action is likely to be taken in respect of Supreme Court Judges whose wards might be practising in the apex court of the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) The Kon'ble Chief Justice of India has not yet made any specific recommendation for transfer of Judges from the High Courts where their wards are practising in the High Courts. However, the Hon'ble Chief Justice of india has indicated that it is appropriate that policy of having one-third of the Judges of the High Courts drawn from outside should be implemented.

(b) Pursuant to the resolution passed at the Chief Justices' Conference of 1992, Hon'ble Chief Justice of India has constituted a Committee of Judges of the Supreme Court and some Chief Justices of the High Courts to examine and lay down norms and put up proposals for transfers in order to assist and advise the Chief Justice of India in this regard.

(c) and (d) Do not arise.

(e) The situation does not arise.

Fiscal Incentives to Private Sector for the Promotion of Renewable Sources of Energy

2050. SHRI S. MADHAVAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is any proposal to give fiscal incentives to private sector to promote new renewable sources of energy ;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the quantum of power expected to be generated through private sector by giving such incentives ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KR1SHNA-KUMAR) : (a) and (b) For attracting private sector investment to promote new & renewable sources of energy, the financial and fiscal incentives, such as soft term loans. accelerated depreciation allowance, excise duty & central sales tax exemptions, concessional customs duty, general sales tax exemption/deferrment, tax holiday for 5 years and capital subsidy are already being provided by the Government. Many of the State Government are also providing facilities of wheeling, banking, third party sale and buy-back of power generated by private enterpreneurs.

(c) During the 8th Plan period 500 to 1000 MW of power generation capacity is expected to be set up through private participation using the financial and fiscal incentives announced by the Central as well as State Governments.

सूक्ष्म लघु जल विद्युत परियोजना

2051. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किन्ही वित्तीय संस्थाओं से सूक्ष्म/लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कोई वित्तीय सहायता अथवा ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या है तथा प्रत्येक संस्था से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और इसमें से मध्य प्रदेश राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान सूक्ष्म/लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को कितनी धन राशि उपलब्ध कराई गयी है ; और

(घ) क्या उपलब्ध कराई गई धनराशि पर्याप्त है ?

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इरेडा को 15 मेवा० स्टेशन क्षमता तक सिंचाई बांध तलहटी और नहर प्रपात आधारित लघु विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से 70.00 मिलियन अमरीकी डालर ऋण उपलब्ध हो गया है । निजी उद्यमियों और विभिन्न राज्यों के सरकारी क्षेत्र के संगठनों को समप दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण उपलब्ध है जो गुण पर आधारित होता है । राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य सरकारों के विभाग ऋण के लिए पात्र नहीं है और राज्य-वार नियतन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को छः चालू लघु विद्युत परियोजनाओं के लिए 340.00 लाख रुपये का आवंटन किया है। इस आवंटन की पर्याप्तता चालू परियोजनाओं की प्रगति और नई परियोजनाओं की जरूरतों पर निर्भर करेगी।

Wind Energy Projects in Gujarat

2052. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAl SHUKLA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the number of wind-energy projects being operated in Gujarat and the capacity of each of the project, location-wise ;

(b) the expenditure incurred on each of the projects ;

(c) whether all the plants are working as per their installed capacity ;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the steps taken by Government to make them fully operational ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE. (SHRT S. KRISHNA KUMAR) : (a) and (b) The details of